रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18, 1970 (चैत्र 28, 1892)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18, 1970 (CHAITRA 28, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 17 मार्च 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 17th March 1970:—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)

—शून्य—

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	397
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	453
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	27
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	489
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	1349
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं ..	1877
भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश ..	191
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	419
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	149
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं..	75
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	233
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	63
पूरक संख्या 16—	
11 अप्रैल 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	671
17 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	681

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	397
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	453
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	27
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	489
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1349
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1877
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	191
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	419
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	149
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	75
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	233
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .	63
SUPPLEMENT No. 16	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 11th April 1970	671
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 17th March 1970	681

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)

मंत्रिमंडल सचिवालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 1970

सं० बी० 11012/1/70-तकनीकी—भारत सरकार के संकल्प (सांख्यिकी विभाग) संख्या डी०एस०/एस०टी०एस०/4-69 दिनांक 5 मार्च 1970 के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के कार्यकलाप के नियमन के लिए तत्काल एक प्रबन्ध परिषद् का गठन किया है । परिषद् की संरचना निम्नलिखित होगी:—

अशासकीय कार्याधिकारी

1. प्रोफेसर वी० एम० दांडेकर, अध्यक्ष
   निदेशक, राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था विषयक
   भारतीय विद्यालय,
   पूना-4
2. डा० बी० पी० अधिकारी, संख्याशास्त्री, सदस्य
   भारतीय सांख्यिकीय संस्थान,
   कलकत्ता ।
3. प्रोफेसर डी० बी० लहिरी, सदस्य
   अनुसंधान प्राध्यापक,
   भारतीय सांख्यिकीय संस्थान,
   कलकत्ता ।
4. प्रोफेसर एम० एल० दांतवाला, सदस्य
   अर्थशास्त्र विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय
   बम्बई-32 ।
5. प्रोफेसर बी० सर्वेश्वर राव, सदस्य
   विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र,
   आन्ध्र विश्वविद्यालय,
   वाल्टेयर, **विशाखापटनम्** ।

सरकारी कार्याधिकारी

6. अर्थशास्त्र एवं आंकड़ा निदेशक, सदस्य
   राजस्थान सरकार,
   जयपुर ।
7. मुख्य आर्थिक सलाहकार, सदस्य
   आर्थिक कार्यविभाग,
   वित्त मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।
8. आर्थिक सलाहकार, सदस्य
   योजना आयोग,
   योजना भवन,
   नई दिल्ली ।
9. निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सदस्य
   नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अधिकारी

10. सर्वेक्षण, अभिकल्प एवं अनुसंधान, आर्थिक विश्लेषण, क्षेत्र संकार्य तथा आंकड़ा-विधायन सहित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के कार्यात्मक प्रभागों के निदेशक । सदस्य
11. मुख्य कार्यनिष्पादन अधिकारी,
    राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन । सदस्य-सचिव

2. प्रबन्ध परिषद् के कार्य वही होंगे जिनका सरकारी संकल्प के उपयुक्त पैरा (कंडिका) 1 में उल्लेख किया गया है । अध्यक्ष पांच वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे जबकि क्रमांक 2 से 8 तक उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश के लागू होने की तारीख से दो वर्ष का होगा ।

3. जब तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती है तब तक प्रबन्ध परिषद् को सचिवालय सहायता केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रदान की जाएगी ।

के० पी० गीताकृष्णन्, उप-सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 1970

संकल्प

सं० ए०-46011/1/70-प्रशासन-1—चौथी योजना में व्यापक महत्व के जिन विभिन्न विशेष कार्यक्रमों का समावेश किया गया है वे हैं : (क) ग्रामीण जनसंख्या के निर्बल वर्गों को लाभान्वित करने के लिए, (ख) सूखे, बंजर और पारिभाषित वर्गों के अन्य क्षेत्र तथा (ग) विकासोन्मुख ग्रामीण रोजगार के निर्माण के लिए सामान्यतया अधिक सुविधाएं । इस प्रकार (1) छोटे परन्तु गतिशील सम्भाव्य किसानों, और (2) उप-सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों के लिए, कुल 115 करोड़ रुपए के योजना कार्यक्रम हैं । ये दोनों ही केन्द्रीय क्षेत्र में हैं । क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए 15 करोड़ रुपए और शुष्क भूमि की खेती के लिए 20 करोड़

रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए, आगामी चार वर्षों में चिरकालीन सूखे क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण के समेकित और सौद्देश्य कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये का गैर-योजना परिव्यय उपलब्ध होने की सम्भावना है। अतः यह आवश्यक है कि इन और समान अन्य कार्यक्रमों पर एक साथ समेकित रूप से विचार कर उन्हें अविलम्ब कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए। यद्यपि कार्यक्रमों के संबंध में प्राशासनिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशो की होगी, फिर भी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिये इन स्कीमों के निरूपण और कार्यान्वयन तथा उनके समय-समय पर समीक्षा व मूल्यांकन में काफी समन्वय की आवश्यकता होगी। एक तरफ सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों तथा दूसरी तरफ संघ स्तर पर कई विभागों तथा एक से अधिक मन्त्रालयों का इन कार्यक्रमों से सम्बन्ध है, अतएव इनके आयोजन, समन्वय और मूल्यांकन में स्वभावतः काफी सीमा तक योजना आयोग को जिम्मेदारी निभानी होगी। तदनुसार भारत सरकार ने निश्चय किया है कि योजना आयोग में ग्रामीण विकास और रोजगार के समन्वय के लिए एक केन्द्रीय समिति का गठन किया जाए। समिति का गठन इस प्रकार किया जाएगा :—

अध्यक्ष

सदस्य (कृषि), योजना आयोग

उपाध्यक्ष

मन्त्रिमण्डल सचिव

सदस्य

निम्नलिखित सचिव

(1) कृषि विभाग,

(2) वित्त (व्यय) विभाग, और

(3) योजना आयोग

सलाहकार (कार्यक्रम प्रशासन), श्री पी० के० जे० मेनन, समिति के सचिव होंगे।

समिति, जब कभी आवश्यक समझे अन्य सम्बद्ध विभागों के भारत सरकार के सचिवों और कृषि पुनर्वित्त निगम तथा ग्रामीण बिजलीकरण निगम के प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकती है।

2. समिति, निम्नलिखित कार्यक्रमो के निरूपण व प्रगति की समीक्षा से विशेष रूप से सम्बन्धित होगी। वह सभी समुचित स्तरों पर उनका समन्वय सुनिश्चित करेगी और उपयुक्त अंतरालों के बाद उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करेगी :

(क) सम्भाव्य गतिशील किसानों के लिए छोटे कृषि विकास ऐजेन्सियों की स्थापना।

(ख) उप-सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिक और ग्रामीण शिल्पियों के लिए समान एजेसियों की स्थापना।

(ग) शुष्क-भूमि कृषि परियोजनाएं।

(घ) चिरकालीन सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण निर्माण कार्य इत्यादि के लिए गैर-योजना परियोजना।

3. ग्रामीण रोजगार के निर्माण और ग्रामीण जनसंख्या के निर्बल वर्गों के लाभ के लिए प्रावाधान करने में निम्नांकित स्कोमें किस सीमा तक महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं, इस सम्बन्ध में भी समिति समीक्षा कर सकती है :

(1) छोटी सिंचाई स्कीमें

(2) ग्रामीण बिजलीकरण स्कीमें

(3) डेरी विकास योजनाएं

(3) क्षेत्र विकास योजनाएं

(5) ग्रामीण शिल्पियों के लिए परियोजनाएं

(6) ग्रामीण सड़क कार्यक्रम

(7) ग्रामीण निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम

(8) विकास केन्द्र

4. समिति अपने काम करने की प्रक्रिया का स्वयं निश्चय करेगी और जितनी बार आवश्यक समझे उतनी बार बैठकें करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, भारतीय बीमा निगम, ग्रामीण बिजलीकरण निगम इत्यादि को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में सर्व-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित कर दिया जाए।

अशोक मित्र, सचिव

स्वास्थ्य, एवं परिवार नियोजन, तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 31 मार्च 1970

संकल्प

विषय —**नैशनल कोडेक्स (खाद्य उत्पाद मानक) समिति**

प०सं० 14-36/67-जन स्वास्थ्य—खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप में "कोडेक्स एलिमेण्टेरियस कमीशन" नामक एक आयोग गठित किया है जिसका उद्देश्य समान विधि से प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर अपनाये गये खाद्य मानकों का संग्रह करना है ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके और खाद्यान्न व्यापार में निष्कपटता सुनिश्चित की जा सके। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सुसंगति लाने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए खाद्यान्नों की परिभाषाएं तथा उनके मानक अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अतः भारत सरकार कोडेक्स एलिमैण्टेरियस कमीशन से सम्पर्क के लिए एक राष्ट्रीय कोडेक्स (खाद्य उत्पाद मानक) समिति का गठन करती है। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

(1) अपर सचिव (उत्पादन)
भारत सरकार,
खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास
एवं सलाहकार मंत्रालय (कृषि विभाग) **अध्यक्ष**

सदस्य

(2) संयुक्त आयुक्त,
डेरी विकास कृषि विभाग ।

(3) पादप संरक्षण सलाहकार, कृषि विभाग

(4) पशु पालन आयुक्त, कृषि विभाग

(5) संयुक्त आयुक्त, मीन उद्योग,
खाद्य विभाग

(6) मुख्य निदेशक,
चीनी एवं वनस्पति, खाद्य विभाग

(7) कृषि पणन सलाहकार, कृषि विभाग

(8) भारतीय मानक संस्थान का एक प्रतिनिधि

(9) विदेश व्यापार (मंत्रालय का एक प्रतिनिधि)

(10) निदेशक, केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, मैसर।

(11) निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता ।

(12) संसाधित खाद्य नियति उन्नयन परिषद्,
119 ओर बाग, नई दिल्ली-3 का एक प्रतिनिधि ।

(13) भारतीय उपभोक्ता परिषद् (राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसधान परिषद्) का एक प्रतिनिधि ।

(14) कार्यकारी निदेशक,
खाद्य एवं पोषण बोर्ड, खाद्य विभाग ।

(15) स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक महानिदेशक एवं इन्चार्ज, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम——सदस्य-सचिव/सम्पर्क अधिकारी ।

सदस्य-सचिव आयोग के सम्पर्क अधिकारी का काम भी करेगा।

राष्ट्रीय कोडेक्स (खाद्य उत्पाद मानक) समिति कोडेक्स एलेमेण्टेरियस कमीशन की वार्षिक बैठकों में विचार किये गये विभिन्न मामलों पर विचार करने तथा उनके लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने के लिए जब कभी आवश्यक हो अपनी बैठकें बुलायेगी। समिति के कार्य में उपभोक्ताओं में वितरित होने वाले सभी प्रमुख खाद्यों के, चाहे वे संसाधित, अर्ध संसाधित अथवा कच्चे हों, मानक सम्मिलित होंगे । इसमें खाद्यों की स्वास्थ्यकारिता, खाद्य योग पेस्टिसाइड अवशेषों, दूषण तत्वों, लेबल लगाने तथा प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण और नमूने लेने की विधियों की योजना सम्मिलित होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री का सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्यों / संघ क्षेत्रों तथा समिति के सरकारी सदस्यों को भेज दी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

अमृत सिंह बावा, उप-सचिव

(परिवार नियोजन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 1970

सं० 5-9/69-स्थापना 2—केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान, नई दिल्ली, जो परिवार नियोजन विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार एक "मूल्यांकन समिति" का गठन करती है ।

2. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

(1) प्रोफेसर बी० कुप्पुस्वामी, निदेशक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, बंगलौर । — अध्यक्ष

(2) प्रोफेसर एम० आर० एन० प्रसाद, जीव-वैज्ञानिक, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली । — सदस्य

(3) डा० पी० के० देवी, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ । — सदस्य

(4) डा० (श्रीमती) ए० जौर्ज, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम — सदस्य

(5) आयुक्त, परिवार नियोजन

(6) श्री टी० आर० पुरी
संयुक्त निदेशक, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग । — सदस्य

(7) डा० एच० बनर्जी, सहायक आयुक्त परिवार नियोजन विभाग । — सदस्य-सचिव

3. इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में इसकी पर्याप्तता तथा कारगरता की दृष्टि से केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान के संगठन और प्रशासन की जांच करना;

(ख) उपलब्ध साधनों और उनकी पर्याप्तता की जांच करना ;

(ग) संस्थान् के कार्यक्रम और उसके द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) संस्थान के आगामी विकास के लिए उपाय सुझाना ।

4. यह समिति अपनी रिपोर्ट छः मास के अन्दर प्रस्तुत करेगी ।

5. समिति को अपनी बैठक में अन्य विशेषज्ञों को चुनने/आमंत्रित करने का अधिकार होगा ।

6. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए समिति के गैर-सरकारी सदस्य यात्रा और दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे । ये भत्ते उन्हें उसी दर के अनुसार दिए जाएंगे जो केन्द्रीय सेवाओं के क्लास 1 के उच्चतम ग्रेड के अधिकारी को स्वीकृत किये जाते हैं । यदि वे वातानुकूलित डिब्बे/हवाई जहाज से यात्रा करना चाहेंगे तो इसके लिए सरकार की पूर्व-अनुमति लेना आवश्यक होगा । समिति के ऐसे सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हैं वे अपने-अपने कार्यालयों से स्वीकृत दरों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते प्राप्त करेंगे ।

7. यह खर्च वर्ष 1969-70 में स्वीकृत बजट के मुख्य शीर्ष "30-सार्वजनिक स्वास्थ्य-ख-5 विविध-ख 5(4)—परिवार नियोजन व्यय ख 5(4) (5)—तकनीकी सलाह एवं पर्यवेक्षण-मुख्यालय तकनीकी कक्ष" से पूरा किया जाएगा और वर्ष 1970-71 का व्यय "30-ख सार्वजनिक स्वास्थ्य ख-5 विविध ख 5(4)—परिवार नियोजन व्यय ख 5(4)(5)—तकनीकी सलाह एवं पर्यवेक्षण ख 5(4) (5)(1)—मुख्यालय तकनीकी कक्ष" शीर्ष के नाम डाला जाएगा बशर्ते कि 1970-71 की निधि के लिए संसद की अनुमति मिल जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यू० एस० राणा, उप-सचिव

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय

नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 1970

सं० 101/69-टी० सी०—भारत सरकार के राजपत्र भाग एक, अनुभाग एक में दिनांक 14 सितम्बर, 1968 को प्रकाशित श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय (नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) की अधिसूचना संख्या 101/68-टी० सी० में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाएगा, अर्थात्:—

"प्रविष्टि सं० 2 में "श्री आई० आर० सेम्युलराज के स्थान पर "लेफ्टीनेन्ट कर्नल डब्लू० सी० कोल"

ग० जगन्नाथ, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Statistics)

New Delhi, the 25th March, 1970

No. V. 11012/1/70-*Tech.*—In pursuance of the Government of India Resolution (Department of Statistics) No. DS/STS/4-69, dated the 5th March 1970, the Government of India have constituted a Governing Council for governing the activities of the National Sample Survey Organisation with immediate effect. The composition of the Council will be as follows :

Non-Officials

Chairman

1. Prof. V. M. Dandekar, Director, Indian School of Political Economy, Poona-4.

Members

2. Dr. B. P. Adhikari, Statistician, Indian Statistical Institute, Calcutta.
3. Prof. D. B. Lahiri, Research Professor, Indian Statistical Institute, Calcutta.
4. Prof. M. L. Dantwala, Department of Economics, Bombay University, Bombay-32.
5. Prof. B. Sarveswara Rao, Head of the Department of Economics, Andhra University, Waltair, Visakhapatnam.

Officials

Members

6. Director of Economics & Statistics, Government of Rajasthan, Jaipur.
7. Chief Economic Adviser, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi.
8. Economic Adviser, Planning Commission, Yojana Bhavan, New Delhi.
9. Director, Central Statistical Organisation, New Delhi.

Officers of the N.S.S. Organisation

10. Directors of functional Divisions of the N.S.S., Organisation, including Survey, Design & Research, Economic Analisis, Field Operations, and Data Processing.

Member-Secretary

11. Chief Executive Officer, National Sample Survey Organisation.

2. The functions of the Governing Council will be as set out in the Government Resolution cited in para 1 above. The Chairman will hold office for a period of five years while the term of office of the members mentioned at Serial Nos. 2 to 8 shall be for a period of two years from the date of this order.

3. The Secretariat assistance to the Governing Council will be provided by the Central Statistical Organisation until suitable arrangements for the purpose are made in the National Sample Survey Organisation.

K. P. GEETHAKRISHNAN, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

RESOLUTION

New Delhi, the 28th March, 1970

No. A. 46011/1/70-*Admn.I.*—The Fourth Plan incorporates various special programmes of large magnitude (a) for the benefit of the weaker sections of the rural population, (b) for the development of dry, arid and other areas of defined categories, and (c) for the creation generally of larger opportunities of development-oriented rural employment. Thus there are Plan programmes totalling Rs. 115 crores for (i) small but potentially viable farmers, and (ii) sub-marginal farmers, agriculture labour and rural artisans. Both these are in the Central sector. There are provisions of Rs. 15 crores for area development schemes and Rs. 20 crores for dry land farming. In addition, a total non-Plan outlay of Rs. 100 crores is expected to be available over the next four years for an integrated and purposive programme of rural works in chronically drought-affected areas. It is important that these and similar programmes should be viewed as an integrated whole and executed efficiently and without delay. While the administrative responsibility for the programmes will of course rest with the State Governments and Union Ministries concerned, their successful execution will involve a considerable measure of coordination in the formulation and implementation of the schemes as well as in their periodical review and evaluation. Since a number of departments and more than one Ministry are involved at the Union level, besides all the State Governments and Union Territories at other levels, the responsibility for planning, coordination and evaluation will naturally, to a large extent, be that of the Planning Commission. Accordingly, the Government of India have decided to set up in the Planning Commission a Central Committee for Coordination of Rural Development and Employment consisting of—

Chairman

Member (Agriculture), Planning Commission.

Vice-Chairman

Cabinet Secretary.

Members

Secretaries of the—

(1) Department of Agriculture,

(2) Ministry of Finance (Expenditure), and

(3) Planning Commission.

Adviser (Programme Administration), Shri P. K. J. Menon will be the Secretary of the Committee.

The Committee may, as and when necessary, co-opt other members including Secretaries to the Government of India of other concerned Departments and representatives of institutions such as the Agricultural Refinance Corporation and the Rural Electrification Corporation.

2. In particular, the Committee will concern itself with the formulation and review of the progress of the following programmes, ensure their coordination at all appropriate stages and arrange for their evaluation at suitable intervals :—

(a) Establishment of Small Farmers Development Agencies for potentially viable farmers.

(b) Establishment of similar agencies for submarginal farmers, agricultural labour and rural artisans.

(c) Dry-land farming projects.

(d) Non-Plan project for integrated rural works etc. in chronically drought affected areas.

3. To the extent the following schemes contribute significantly to the creation of rural employment and provision of benefits to the weaker sections of the rural population, the Committee may also review :—

(i) Minor Irrigation Schemes.

(ii) Rural Electrification Schemes.

(iii) Dairy Development Schemes.

(iv) Area Development Schemes.

(v) Projects for Rural Artisans.

(vi) Rural Roads Programmes.

(vii) Other Programmes Involving Rural Works.

(viii) Growth Centres.

4. The Committee will devise its own procedures and meet as often as required.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India, all State Governments, Reserve Bank of India, State Bank of India, Life Insurance Corporation, Agricultural Refinance Corporation, Rural Electrification Corporation etc.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. MITRA, Secy.

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 1st April, 1970

SUBJECT.—*Long Vacation*—1970.

No. F. 44/70-SCA(G).—In pursuance of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966, the Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to direct that the Supreme Court will be closed for the Annual Summer Vacation from Monday, the 11th May, 1970 to Sunday, the 19th July, 1970 (both days inclusive) and will re-open on Monday, the 20th July, 1970.

Under Rule 6 of Order II of the aforesaid Rules, the Hon'ble the Chief Justice of India has been further pleased to appoint the Hon'ble Mr. Justice A. N. Ray and the Hon'ble Mr. Justice I. D. Dua to be Vacation Judges to hear matters of an urgent nature, which under the above Rules may be heard by a Judge sitting singly during the periods shown against their names below :—

The Hon'ble Mr. Justice A. N. Ray from 11th May to 14th June, 1970 (both days inclusive)

The Hon'ble Mr. Justice I. D. Dua from 15th June to 19th July, 1970 (both days inclusive)

The Hon'ble Mr. Justice A. N. Ray will sit in the Court on Tuesdays, the 26th May and 9th June, 1970 and the Hon'ble Mr. Justice I. D. Dua on Tuesdays, the 23rd June and 7th July, 1970. Sittings will, however, continue on the next succeeding days if matters fixed for any day are not finished on that day.

Except on Saturdays, Sundays and holidays, the Offices of the Court shall be open during vacation between 8 A.M. and 12.30 P.M. daily; but on the days notified for the vacation sittings, the office shall be open from 10 A.M. to 4 P.M.

No plaints, appeals, petitions or other documents except those which require to be immediately or promptly dealt with, will be filed or received in the Registry of the Court during the above period of vacation. For the convenience of the parties, however, the Registry will receive all plaints, appeals, petitions and other documents from 13th July, 1970 onwards during office hours.

C. V. RANE, Registrar

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING, WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Health)

New Delhi, the 31st March, 1970

RESOLUTION

SUBJECT :—*National Codex (Food Products Standards) Committee.*

No. F. 14-36/67-PH.—The Food & Agricultural Organisation and the World Health Organisation have jointly sponsored a Commission called the "Codex Alimentarius Commission", whose objectives are the collection of internationally adopted food standards presented in a uniform manner so as to protect the consumer's health and ensure fair practice in food trade. As the definitions and standards of food to assist harmonization and facilitate the international trade are of vital interest the Government of India are pleased to constitute a National Codex (Food Products Standards) Committee for liaison with the Codex Alimentarius Commission. The composition of the Committee shall be as follows :—

Chairman

(1) Additional Secretary to the Government of India (Production) Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture).

Members

(2) Joint Commissioner Dairy Development, Department of Agriculture.

(3) Plant Protection Adviser, Department of Agriculture.

(4) Animal Husbandry Commissioner, Department of Agriculture.

(5) Joint Commissioner, Fisheries, Department of Food

(6) Chief Director, Sugar & Vanaspati, Department of Food.

(7) Agricultural Marketing Adviser, Department of Agriculture.

(8) A representative of the Indian Standards Institution.

(9) A representative of the Ministry of Foreign Trade.

(10) Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore.

(11) Director, Central Food Laboratory, Calcutta.

(12) A representative of the Processed Foods Exports Promotion Council, 119 Jor Bagh, New Delhi-3.

(13) A representative of the Consumer Council of India (National Council of Applied Economic Research)

(14) Executive Director, Food & Nutrition Board, Department of Food.

Member-Secretary/Liaison Officer.

(15) Assistant Director General of Health Services Incharge of Prevention of Food Adulteration Act.

The Member-Secretary will also work as the Liaison Officer for the Committee.

The National Codex (Food Products Standards) Committee shall meet as and when necessary to consider the various issues that may be discussed at the annual meetings of the Codex Alimentarius Commission and to prepare necessary material therefor. The work of the Committee will include standards for all the principal foods, whether processed,

semi-processed or raw for distribution to the consumers. It will include provision in respect of food hygiene, food additives, pesticide residues, contaminants, labelling and presentation, methods of analysis and sampling.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Secretary to the President; the Prime Minister's Secretariat; the Cabinet Secretariat; the Planning Commission; all Ministries of the Government of India; all State Governments and Governments of Union Territories; Government Members of the Committee

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. S. BAWA, Dy. Secy.

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 31st March, 1970

RESOLUTION

No. 5-9/69-Estt.II.—The Government of India are pleased to constitute an "Evaluation Committee" for evaluating the work of the Central Family Planning Institute, New Delhi, an autonomous body under the Department of Family Planning.

2. The composition of the Committee will be as under :—

Chairman

(i) Prof. B. Kuppuswamy Director Institute for Social and Psychological Research, Bangalore.

Members

(ii) Prof. M. R. N. Prasad, Biologist, Delhi University, Delhi.

(iii) Dr. P. K. Devi, Post-graduate Institute of Medical Education Research, Chandigarh.

(iv) Dr. (Mrs.) A. George, University of Kerala, Trivandrum.

(v) Commissioner, Family Planning.

(vi) Shri T. R. Puri, Joint Director, Programme Evaluation Organisation, Planning Commission

Member-Secretary

(vii) Dr. H Banerjee, Assistant Commissioner, Department of Family Planning.

3. The functions of this Committee shall be as follows :—

(a) to examine the Organisational and administrative set up of the Central Family Planning Institute from the point of view of its adequacy and affectiveness as a National Family Planning Training and Research Institute;

(b) to examine the resources available and their adequacy;

(c) to assess programme and progress made by the Institute; and

(d) to suggest ways and means for further development of the Institute.

4. The Committee will submit its report within six months.

5. The Committee will have the power to cooperate/invite other experts to attend its meetings.

6. Non-official members of the Committee shall be entitled to the grant of travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committee at the rate admissible to an officer of the highest grade in Class I of the Central Services. In case they wish to travel by Air Conditioned Coach/air, prior permission of the Government will be necessary Members of the Committee who are Government servants will draw travelling and daily allowances as admissible to them from the same source from which they get their salary.

7 The expenditure involved is to be met from within the sanctioned budget under Major Head "30-Public Health B-5. Miscellaneous B5(4)—Expenditure on Family Planning B.5(4)(5)—Technical Advise and Supervision—Technical Wing at Head quarters" during 1969-70 and the expenditure during 1970-71 is to be debited to the Head "30-B. Public Health B-5 Miscellaneous B 5(4)—Expenditure on Family Planning B.5(4)(5)—Technical Advise and Supervision B 5(4)(5)(1)-Technical Wing at Head quarters" subject to the funds for 1970-71 being voted by the Parliament.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India.

U. S. RANA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi the 30th March, 1970

No. 23/12/69-LI.—The President hereby directs that, with effect from the 1st April, 1970, the following further amendments shall be made in the Rules relating to Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely :—

In the said rules,—

(1) in rule 13, (i) in clause (a), for the words and figures "age of either 50 or 55 or 60 or 70 years", the words and figures "age of 50, 55, 58, 60 or 70 years" shall be *substituted;* (ii) in clause (b), for the words and figures "age of 40, 45, 50, 55 or 60 years", the words and figures "age of 40, 45, 50, 55, 58 or 60 years" shall be *substituted;*

(2) after Tables I and II at the end of rule 43, the following Tables shall be added, namely :—

TABLE III

Post Office Insurance Fund—Premiums in Force from the 1st April 1970

Whole Life Assurance

Monthly Premium for an Assurance of Rs. 1,000

Age at entry	*Premiums ceasing at the age of 58.*
	Rs. P.
19	1 50
20	1 55
21	1 60
22	1 65
23	1 70
24	1 75
25	1 80
26	1 85
27	1 90
28	2 00
29	2 10
30	2 20
31	2 30
32	2 40
33	2 50
34	2 60
35	2 75
36	2 90
37	3 05
38	3 20
39	3 40
40	3 60
41	3 85
42	4 10
43	4 40
44	4 70
45	5 10
46	5 50

47	6 05
48	6 65
49	7 40
50	8 30

NOTE 1.—For the purpose of this table "age at entry" means the age next birthday following the date of payment of the first premium.

NOTE 2.—For a policy of Rs 4,000 or above rebate at the rate of 5 paise per month per thousand sum assured is allowed

NOTE 3.—Wherever the monthly premium arrived at for a policy is not in multiples of 5 paise, it would be rounded off to the next higher 5 paise unit

TABLE IV

Post Office Insurance Fund—Premiums In Force from the 1st April 1970

Endowment Assurance

Monthly Premium for an Assurance of Rs. 1,000

Age at entry	*Maturity age 58.*
	Rs P.
19	1 90
20	1 95
21	2 00
22	2 05
23	2 10
24	2 20
25	2 30
26	2 40
27	2 50
28	2 60
29	2 70
30	2 80
31	2 95
32	3 10
33	3 25
34	4 40
35	3 55
36	3 75
37	3 95
38	4 20
39	4 45
40	4 70
41	5 00
42	5 35
43	5 75
44	6 20
45	6 70
46	7 30
47	8 00
48	8 80
49	9 80
50	11 10

NOTE 1.—For the purpose of this table "age at entry" means the age next birthday following the date of payment of the first premium.

NOTE 2.—For a policy of Rs. 4,000 or above rebate at the rate of 5 paise per month per thousand sum assured is allowed

NOTE 3.—Wherever the monthly premium arrived at for a policy is not in multiples of 5 paise, it would be rounded off to the next higher 5 paise unit

R. KISHORE
Director, Postal Life Insurance

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 31st March, 1970

No 101/69-*TC*.—The following amendment shall be made in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment (Director General of Employment and Training) Notification No. 101/68-TC published in the Gazette of India, Part-I, Section-1 dated the 14th September, 1968, namely :—

"Against entry No 2 substitute 'Lt. Col W C Cole' in place of 'Shri I R. Samuel Raj'

G. JAGANNATHAN, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970